Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-7| July-2026

Original Article

भारत–चीन–पाकिस्तान त्रिकोणीय संबंधों का बदलता परिदृश्य और भारतीय विदेश नीति: 1990 के बाद का अध्ययन

शरद पंडित पाटिल[1], डॉ. उमेश अशोक गोगडीया[2]

[1]शोध छात्र, राजनीती विज्ञान विभाग, क.ब.चौ. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जलगाँव

[2]सह-प्राध्यापक एवं विभाग प्रमुख, राजनीती विज्ञान विभाग, क.ब.चौ. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जलगाँव

Manuscript ID:
JRD -2026-180720
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 7
Pp. 98-104
July- 2026
Submitted: 15 June. 2026
Revised: 25 June. 2026
Accepted: 10 July. 2026
Published: 31 July. 2026

सार

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 1990 के दशक के बाद व्यापक परिवर्तन देखने को मिले। भारत–चीन–पाकिस्तान त्रिकोणीय संबंधों को शीत युद्ध की समाप्ति, वैश्वीकरण का विस्तार, चीन का तीव्र आर्थिक एवं सैन्य उत्थान और दक्षिण एशिया की बदलती सामरिक परिस्थितियों ने नई दिशा प्रदान की। साल 1990 के पश्चात चीन एवं पाकिस्तान के बीच तकनीकी, सामरिक और आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप दक्षिण एशिया की शक्ति-संतुलन व्यवस्था प्रभावित हुई। विशेष रूप से चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), रक्षा प्रौद्योगिकी, परमाणु सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की सक्रियता ने भारत के सामने नई सामरिक तथा कूटनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न कीं। भारत ने इन परिवर्तनों के जवाब में अपनी विदेश नीति में बहुआयामी परिवर्तन करते हुए "लुक ईस्ट" से "एक्ट ईस्ट" नीति, पड़ोसी प्रथम नीति, हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण, क्वाड में सहभागिता, सामरिक साझेदारियों का विस्तार और रक्षा आधुनिकीकरण जैसे कई अहम कदम उठाए। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य साल 1990 के बाद भारत–चीन–पाकिस्तान त्रिकोणीय संबंधों के बदलते स्वरूप का विश्लेषण करना और भारतीय विदेश नीति पर उसके प्रभावों का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बदलते भू-राजनीतिक परिवेश में भारत की विदेश नीति अधिक राष्ट्रीय हित-आधारित, यथार्थवादी, संतुलित और बहुध्रुवीय बनकर उभरी है।

कुंजी शब्द: *भारत–चीन संबंध, भारत–पाकिस्तान संबंध, भारतीय विदेश नीति, सामरिक प्रतिस्पर्धा*

भूमिका:

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देशों के बीच संबंध निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं तथा इन परिवर्तनों का प्रभाव उनकी विदेश नीति पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। दक्षिण एशिया में भारत, चीन तथा पाकिस्तान तीन ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जिनके परस्पर संबंध सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एशियाई एवं वैश्विक शक्ति-संतुलन को भी प्रभावित करते हैं। साल 1990 के बाद वैश्विक शक्ति-संरचना में आए परिवर्तनों के साथ चीन एक प्रमुख आर्थिक एवं सैन्य शक्ति के तौर पर उभरा, जबकि पाकिस्तान ने अपनी सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चीन के साथ सहयोग को और मज़बूत किया। इस बीच भारत ने वैश्विक सहभागिता, आर्थिक उदारीकरण, बहुपक्षीय कूटनीति और रणनीतिक साझेदारियों को अपनाते हुए अपनी विदेश नीति को नए आयाम प्रदान किए।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
शरद पंडित पाटिल, शोध छात्र, राजनीती विज्ञान विभाग, क.ब.चौ. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जलगाँव

How to cite this article:
पाटिल, शरद. पंडित. & गोगडीया, उमेश. अशोक. (2026). भारत–चीन–पाकिस्तान त्रिकोणीय संबंधों का बदलता परिदृश्य और भारतीय विदेश नीति: 1990 के बाद का अध्ययन. Journal of Research and Development, 18(7), 98–104. https://doi.org/10.5281/zenodo.21942340

Quick Response Code:

Website:
https://jrdrvb.org/

DOI:
10.5281/zenodo.21942340

OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-7| July-2026

वर्तमान समय में आतंकवाद, सीमा विवाद, हिंद-प्रशांत रणनीति, परमाणु प्रतिरोध, चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और समुद्री सुरक्षा जैसे विषय इस त्रिकोणीय संबंध के प्रमुख निर्धारक बन चुके हैं। अतः इन परिवर्तनों का समग्र अध्ययन भारतीय विदेश नीति की दिशा एवं भविष्य को समझने हेतु बेहद ज़रूरी है।

शोध के उद्देश्य:

1. भारत–चीन–पाकिस्तान के बीच वर्ष 1990 के बाद विकसित होते त्रिकोणीय संबंधों के स्वरूप और उनके परिवर्तनशील आयामों का विश्लेषण करना।
2. चीन–पाकिस्तान के बीच विकसित सामरिक और आर्थिक सहयोग के भारत की विदेश नीति, सुरक्षा हितों एवं क्षेत्रीय रणनीतिक परिदृश्य पर पड़ने वाले प्रभावों का समग्र अध्ययन करना।
3. भारत द्वारा अपनाई गई प्रमुख कूटनीतिक तथा सामरिक नीतियों एवं रणनीतियों का मूल्यांकन करना, जिनके ज़रिये उसने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना किया है।
4. समकालीन अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दक्षिण एशिया तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका, प्रभाव एवं रणनीतिक महत्व का अध्ययन करना।

शोध का महत्व:

1. दक्षिण एशिया की समकालीन भू-राजनीतिक परिस्थितियों और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन को समझने में प्रस्तुत शोध महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।
2. प्रस्तुत अध्ययन भारतीय विदेश नीति में समय के साथ हुए संरचनात्मक तथा रणनीतिक परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करेगा और उनके प्रभावों को स्पष्ट करेगा।
3. प्रस्तुत शोध भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक हितों और समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का अकादमिक तथा विश्लेषणात्मक मूल्यांकन उपलब्ध कराएगा।
4. भविष्य के शोधार्थियों, शिक्षाविदों एवं नीति-निर्माताओं हेतु प्रस्तुत अध्ययन संदर्भ सामग्री के तौर पर उपयोगी सिद्ध होगा और क्षेत्रीय तथा वैश्विक रणनीतिक अध्ययन में योगदान देगा।

शोध का योगदान:

1. प्रस्तुत शोध भारत–चीन–पाकिस्तान संबंधों का समग्र, व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।
2. प्रस्तुत अध्ययन वर्ष 1990 के बाद भारतीय विदेश नीति में हुए प्रमुख परिवर्तनों और उनके रणनीतिक प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करता है।
3. प्रस्तुत शोध समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भारत की विकसित होती रणनीतिक भूमिका और उसके वैश्विक महत्व को स्पष्ट करता है।
4. प्रस्तुत अध्ययन दक्षिण एशिया में परिवर्तित होते शक्ति-संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और सामरिक गतिशीलताओं को एक नवीन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है।

विश्लेषण:

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वर्ष 1990 के बाद एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, जिसने एशिया की सामरिक राजनीति को भी गहराई से प्रभावित किया। इसी दौरान चीन की आर्थिक प्रगति, पाकिस्तान के साथ उसकी रणनीतिक निकटता और भारत की आर्थिक उदारीकरण नीति ने दक्षिण एशिया की शक्ति-संरचना को पुनर्परिभाषित किया। भारत–चीन–पाकिस्तान संबंध अब सिर्फ सीमा विवाद अथवा द्विपक्षीय संघर्षों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, आर्थिक संपर्क, आतंकवाद, ऊर्जा मार्गों, वैश्विक संस्थाओं एवं तकनीकी प्रतिस्पर्धा तक विस्तारित हो चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य एवं भारत–चीन संबंधों का परिवर्तित स्वरूप:

वैश्विक राजनीति में सोवियत संघ के विघटन (1991) के बाद व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन हुए। शीत युद्ध की द्विध्रुवीय व्यवस्था की समाप्ति के बाद अमेरिका एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरा, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में बहुध्रुवीयता की प्रवृत्ति भी धीरे-धीरे विकसित होने लगी। इस परिवर्तित वैश्विक परिदृश्य में भारत ने अपनी पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति को बनाए रखते हुए आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों को अपनाया, जिसके फलस्वरूप भारत की वैश्विक आर्थिक एवं कूटनीतिक भूमिका में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। इसी दौरान चीन ने तीव्र आर्थिक विकास, वैश्विक व्यापार विस्तार, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और सैन्य

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-7| July-2026

आधुनिकीकरण की नीतियों के ज़रिये अपनी क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्थिति को मज़बूत किया। चीन की बढ़ती आर्थिक एवं सामरिक क्षमताओं ने एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शक्ति-संतुलन व्यवस्था को प्रभावित किया। वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं तथा सामरिक हितों को मद्देनज़र रखते हुए चीन के साथ रक्षा, आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग को और मज़बूत किया। फलस्वरूप, दक्षिण एशिया में भारत–चीन–पाकिस्तान के बीच एक जटिल त्रिकोणीय शक्ति-संतुलन व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिसने क्षेत्रीय भू-राजनीतिक गतिशीलताओं को नया स्वरूप प्रदान किया।

1990 के दशक में भारत एवं चीन ने सीमा विवादों के बावजूद आर्थिक तथा कूटनीतिक संबंधों को विकसित करने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए और व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। दोनों देशों के संबंधों में आर्थिक सहयोग ने स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, समय के साथ सीमा विवाद, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। डोकलाम गतिरोध (2017) एवं गलवान संघर्ष (2020) जैसी घटनाओं ने भारत–चीन संबंधों को पुनः तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया। इसके इलावा, चीन की क्षेत्रीय विस्तारवादी नीतियाँ, हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सामरिक गतिविधियाँ, बंदरगाह विकास परियोजनाएँ और बेल्ट एंड रोड पहल भारत की सुरक्षा एवं सामरिक चिंताओं के प्रमुख विषय बने। इन चुनौतियों के जवाब में भारत ने सीमावर्ती अवसंरचना के विकास, रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण, सामरिक साझेदारियों के विस्तार और समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग को प्राथमिकता दी। इस प्रकार, शीत युद्धोत्तर काल में भारत–चीन संबंध सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के मिश्रित स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। आर्थिक परस्पर निर्भरता के साथ-साथ सुरक्षा हितों, क्षेत्रीय प्रभाव तथा सामरिक प्रतिस्पर्धा ने इन संबंधों को जटिल एवं बहुआयामी बना दिया है, जिसका प्रभाव न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों पर बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशियाई भू-राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ा है।

चीन–पाकिस्तान सामरिक साझेदारी एवं भारत–पाकिस्तान संबंधों पर चीन का प्रभाव:

चीन एवं पाकिस्तान के बीच विकसित हुई सामरिक साझेदारी समय के साथ अधिक बहुआयामी, गहन और व्यापक स्वरूप ग्रहण करती गई है। दोनों देशों के संबंध सिर्फ पारंपरिक कूटनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सुरक्षा, रक्षा, तकनीकी सहयोग, आर्थिक निवेश और आधारभूत संरचना विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक विस्तारित हुए हैं। चीन ने पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों, रक्षा उत्पादन, परमाणु ऊर्जा सहयोग, मिसाइल तकनीक एवं रणनीतिक अवसंरचना निर्माण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। इस सहयोग ने दोनों देशों के बीच आपसी रणनीतिक निर्भरता को मज़बूत किया है। चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इस साझेदारी का एक प्रमुख आयाम बनकर उभरा है, जिसने आर्थिक सहयोग को सामरिक महत्व प्रदान किया है। यह परियोजना चीन की व्यापक बेल्ट एंड रोड पहल का एक अहम हिस्सा है तथा इसका उद्देश्य व्यापारिक मार्गों, क्षेत्रीय संपर्क और अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि, भारत ने इस परियोजना पर आपत्ति व्यक्त की है क्योंकि इसका एक भाग पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर क्षेत्र से होकर गुज़रता है। भारत के अनुसार, यह विषय उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित गंभीर रणनीतिक चिंताओं को उत्पन्न करता है।

भारत और पाकिस्तान के संबंध ऐतिहासिक तौर पर कश्मीर मुद्दे, सीमा विवाद, आतंकवाद और पारस्परिक अविश्वास जैसे कारकों से प्रभावित रहे हैं। वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद दोनों देशों के बीच सामरिक संतुलन एवं सुरक्षा गतिशीलताओं में अहम बदलाव आया। इसके बाद कारगिल युद्ध (1999), संसद पर आतंकवादी हमला (2001), मुंबई आतंकवादी हमला (2008) एवं सीमा पार आतंकवाद से संबंधित घटनाओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और भी जटिल बना दिया। इन परिस्थितियों में चीन ने विभिन्न अवसरों पर पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक समर्थन प्रदान किया, जिससे दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था और भी जटिल हुई। चीन–पाकिस्तान की निकटता ने भारत हेतु क्षेत्रीय सुरक्षा, सामरिक संतुलन और दो मोर्चों पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को अधिक गंभीर बना दिया। फलस्वरूप, भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक तैयारियों को बढ़ाने और क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सामरिक साझेदारियों को विस्तार देने की नीति अपनाई।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-7| July-2026

भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नई सामरिक प्रतिस्पर्धा:

वर्ष 1990 के बाद भारतीय विदेश नीति में व्यापक एवं संरचनात्मक बदलाव देखने को मिले। शीत युद्ध के समापन, वैश्विक शक्ति-संतुलन में परिवर्तन और नई आर्थिक चुनौतियों के कारण भारत ने अपनी विदेश नीति को अधिक व्यावहारिक, बहुआयामी तथा राष्ट्रीय हितों पर आधारित बनाया। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी को बढ़ाया और अमेरिका, जापान, रूस, यूरोपीय देशों एवं अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ रणनीतिक, आर्थिक एवं तकनीकी संबंधों को मज़बूत किया। भारत ने बदलते अंतरराष्ट्रीय परिवेश के अनुरूप अपनी क्षेत्रीय एवं वैश्विक भूमिका का विस्तार किया। पूर्वी एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मज़बूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई "लुक ईस्ट" नीति को आगे बढ़ाते हुए "एक्ट ईस्ट" नीति को अपनाया गया। इस नीति के ज़रिये भारत ने आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय संपर्क, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा प्रदान की। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत ने मुक्त एवं समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा, मुक्त नौवहन और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अपनी विदेश नीति के प्रमुख आधारों के तौर पर स्थापित किया।

भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अन्य देशों के साथ रक्षा, तकनीकी एवं सामरिक सहयोग का विस्तार किया। इन सहयोगों का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना, सामरिक संतुलन को मज़बूत करना और उभरती सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना रहा। हिंद-प्रशांत क्षेत्र वर्तमान वैश्विक राजनीति में सामरिक प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। इस क्षेत्र का बढ़ता आर्थिक एवं भू-राजनीतिक महत्व प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का आधार बना है। चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति, दक्षिण चीन सागर में उसकी गतिविधियाँ और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव भारत की समुद्री एवं सामरिक सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। इसके इलावा, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का विकास और चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं ने भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को और भी गंभीर बनाया है। इन परिस्थितियों के जवाब में भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मज़बूत किया, अंडमान एवं निकोबार कमान की रणनीतिक भूमिका को बढ़ाया और क्षेत्रीय एवं वैश्विक समुद्री साझेदारियों का विस्तार किया। भारत ने क्वाड (QUAD), ब्रिक्स (BRICS), शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय मंचों के ज़रिये भी अपनी कूटनीतिक सक्रियता को बढ़ाया है। इस प्रकार, वर्ष 1990 के बाद भारतीय विदेश नीति ने पारंपरिक गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए एक सक्रिय, रणनीतिक और बहुआयामी स्वरूप ग्रहण किया है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वैश्विक शक्ति-संतुलन, समुद्री सुरक्षा एवं नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने वाला देश बन गया है।

क्वाड, बहुपक्षीय कूटनीति एवं भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ:

हिंद-प्रशांत क्षेत्र इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में वैश्विक सामरिक प्रतिस्पर्धा के प्रमुख केंद्र के तौर पर उभरा। चीन की बढ़ती समुद्री सक्रियता, दक्षिण चीन सागर में उसका प्रभाव विस्तार और बेल्ट एंड रोड पहल के ज़रिये विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते प्रभाव ने क्षेत्रीय एवं वैश्विक शक्ति-संतुलन को प्रभावित किया। इन परिस्थितियों में भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue) का महत्व बढ़ा। भारत ने क्वाड को किसी देश के खिलाफ सैन्य गठबंधन के तौर पर प्रस्तुत करने के बजाय एक सहयोगात्मक मंच के रूप में देखा, जिसका उद्देश्य मुक्त, समावेशी, सुरक्षित और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था को बढ़ावा देना है। क्वाड के ज़रिये भारत ने समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, साइबर सुरक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहयोग और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी की। चीन ने क्वाड को अपने क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से गठित एक रणनीतिक पहल के तौर पर देखा, जबकि भारत ने इसे अपनी बहुआयामी एवं संतुलित विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग माना। इस प्रकार, क्वाड भारत की सामरिक कूटनीति का एक प्रमुख माध्यम बनकर उभरा, जिसके द्वारा भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता एवं रणनीतिक संतुलन को बढ़ावा देने की कोशिश की।

वैश्विक राजनीति में वर्ष 1990 के बाद बहुपक्षीय संगठनों की भूमिका में निरंतर वृद्धि हुई। भारत, चीन एवं पाकिस्तान ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मंचों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हितों, आर्थिक विकास और सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया। भारत ने ब्रिक्स (BRICS), जी-20 (G20), बिम्सटेक (BIMSTEC), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और क्वाड जैसे

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-7| July-2026

मंचों के ज़रिये अपनी वैश्विक भूमिका का विस्तार किया। वहीं दूसरी ओर, चीन ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO), ब्रिक्स, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) और बेल्ट एंड रोड पहल के ज़रिये अपने आर्थिक एवं सामरिक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया। पाकिस्तान ने मुख्य रूप से चीन के सहयोग से शंघाई सहयोग संगठन और चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसे माध्यमों द्वारा अपनी क्षेत्रीय प्रासंगिकता को बनाए रखने की कोशिश की। भारत की बहुपक्षीय कूटनीति की प्रमुख विशेषता यह रही है कि उसने प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विभिन्न मंचों का उपयोग अपने रणनीतिक एवं आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु किया। भारत ने किसी एक शक्ति समूह पर निर्भर होने के बजाय बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में स्वतंत्र एवं संतुलित विदेश नीति को प्राथमिकता दी।

सीमा विवाद भारत–चीन संबंधों में वर्तमान समय की प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों में से एक बना हुआ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर समय-समय पर उत्पन्न तनाव, सैन्य तैनाती और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना विकास ने दोनों देशों के बीच विश्वास को प्रभावित किया है। डोकलाम गतिरोध (2017) तथा गलवान घाटी संघर्ष (2020) जैसी घटनाओं ने यह स्पष्ट किया कि सीमा विवाद सिर्फ क्षेत्रीय प्रश्न भर नहीं है, बल्कि इसका व्यापक सामरिक एवं राजनीतिक महत्व भी है। इसी प्रकार, भारत–पाकिस्तान संबंधों में नियंत्रण रेखा (LoC) पर तनाव, सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ निरंतर बनी रही हैं। इन परिस्थितियों ने भारत के समक्ष दो मोर्चों पर सुरक्षा तैयारियों की आवश्यकता को बढ़ाया है। फलस्वरूप, भारत ने रक्षा आधुनिकीकरण, सैन्य क्षमता विकास, सीमावर्ती अवसंरचना निर्माण और रणनीतिक साझेदारियों के विस्तार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया है।

इस प्रकार, क्वाड एवं बहुपक्षीय कूटनीति के ज़रिये भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक भूमिका को मज़बूत किया है, जबकि सीमा विवादों और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच अपनी रक्षा एवं सामरिक क्षमताओं को निरंतर विकसित किया है।

आर्थिक आयाम, बदलती प्राथमिकताएँ एवं भविष्य की संभावनाएँ:

भारत–चीन–पाकिस्तान त्रिकोणीय संबंधों में आर्थिक कारकों की भूमिका शीत युद्धोत्तर काल में लगातार बढ़ती गई है। आर्थिक शक्ति अब सिर्फ विकास का माध्यम मात्र नहीं रही, बल्कि यह भू-राजनीतिक प्रभाव, सामरिक क्षमता एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण आधार भी बन चुकी है। चीन ने तीव्र आर्थिक विकास के ज़रिये खुद को विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित किया है और एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश एवं अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के ज़रिये अपने आर्थिक प्रभाव का विस्तार किया है। चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसी रणनीतिक दृष्टिकोण का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को सामरिक आयाम प्रदान किया है। चीन की बढ़ती आर्थिक एवं रणनीतिक सक्रियता के जवाब में भारत ने अपने आर्थिक एवं सामरिक हितों की सुरक्षा हेतु विभिन्न पहलें शुरू की हैं। चाबहार बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने जैसी नीतियाँ इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। वर्तमान समय में आर्थिक कूटनीति भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ बन चुकी है, जिसके ज़रिये भारत निवेश, व्यापार, तकनीकी सहयोग और वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को मज़बूत कर रहा है।

भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकताओं में भी वर्ष 1990 के बाद अहम बदलाव हुए हैं। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व प्रदान करते हुए आर्थिक विकास, रणनीतिक स्वायत्तता तथा वैश्विक सहयोग के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। भारत ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के समर्थन, आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय एवं रचनात्मक भूमिका निभाने को अपनी विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया है। इसके इलावा, भारत ने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क एवं सहयोग बढ़ाने, नई प्रौद्योगिकियों के विकास, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष कूटनीति तथा रक्षा आधुनिकीकरण को भी अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं का हिस्सा बनाया है। इन नीतिगत परिवर्तनों ने भारत को एक उत्तरदायी, प्रभावशाली एवं उभरती वैश्विक शक्ति के तौर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है।

समकालीन परिस्थितियों में भारत–चीन–पाकिस्तान संबंध दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति एवं सुरक्षा व्यवस्था को निरंतर प्रभावित करते रहेंगे। चीन का आर्थिक एवं सैन्य विस्तार, पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीतियाँ, सीमा विवाद, आतंकवाद, जल सुरक्षा, साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री प्रतिस्पर्धा और वैश्विक शक्ति-संतुलन जैसे कारक इस त्रिकोणीय संबंधों के

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-7| July-2026

भविष्य को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएँगे। भविष्य में भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती यह होगी कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करे। प्रभावी कूटनीति, आर्थिक सुदृढ़ीकरण, तकनीकी नवाचार, रक्षा क्षमता विकास तथा क्षेत्रीय सहयोग के ज़रिये भारत इस त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप दिशा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार, भारत की भविष्य की भूमिका सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित न रहकर वैश्विक शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने वाली एक अहम शक्ति के तौर पर विकसित होने की संभावना रखती है।

नीतिगत सुझाव:

1. भारत को अपनी पड़ोसी नीति को अधिक विश्वास-आधारित, सक्रिय और समावेशी बनाना चाहिए, ताकि पारस्परिक विश्वास, स्थिरता तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
2. सीमा क्षेत्रों में रक्षा क्षमताओं, आधुनिक अवसंरचना और सैन्य तैयारियों का निरंतर विकास किया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।
3. भारत को आर्थिक कूटनीति को और भी मज़बूत करते हुए आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक व्यापारिक साझेदारियों, तकनीकी सहयोग और विदेशी निवेश में अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहिए।
4. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने हेतु भारत को अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मंचों पर अपनी सक्रिय भागीदारी को और मज़बूत करना चाहिए।
5. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियों का सामना करने हेतु भारत को वैश्विक सहयोग तथा रणनीतिक साझेदारियों को और भी प्रभावी बनाना चाहिए।

निष्कर्ष:

1. वर्ष 1990 के बाद भारत–चीन–पाकिस्तान त्रिकोणीय संबंधों में संरचनात्मक एवं व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिनका काफी हद तक प्रभाव दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय विदेश नीति की दिशा पर पड़ा है।
2. चीन–पाकिस्तान के बीच बढ़ती आर्थिक एवं सामरिक साझेदारी (विशेष रूप से रक्षा सहयोग तथा चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसी पहलों के कारण) भारत हेतु दीर्घकालीन सुरक्षा एवं कूटनीतिक चुनौती बनी हुई है।
3. बदलते क्षेत्रीय एवं वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप भारत ने अपनी विदेश नीति को अधिक राष्ट्रीय हित-आधारित, व्यावहारिक और बहुआयामी स्वरूप प्रदान किया है।
4. भारत ने बहुपक्षीय मंचों, आर्थिक कूटनीति, रक्षा आधुनिकीकरण और सामरिक साझेदारियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपनी वैश्विक भूमिका को मज़बूत किया है।
5. आर्थिक सहयोग, हिंद-प्रशांत क्षेत्र, बहुपक्षीय कूटनीति और समुद्री सुरक्षा भारतीय विदेश नीति के प्रमुख स्तंभों के तौर पर उभरे हैं।
6. भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय देशों और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ सहयोग को विस्तार दिया है।
7. आतंकवाद, सीमा विवाद, उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन जैसी चुनौतियाँ भारत की सुरक्षा एवं विदेश नीति हेतु महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।
8. भारत आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रभावी कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व के बीच संतुलन किस तरह स्थापित करता है, इस बात पर भविष्य में भारत की सफलता निर्भर करेगी।
9. यदि भारत अपनी आर्थिक शक्ति, तकनीकी नवाचार, सामरिक क्षमताओं और क्षेत्रीय सहयोग को लगातार सुदृढ़ करता है, तो वह दक्षिण एशिया और वैश्विक राजनीति में एक प्रभावशाली शक्ति के तौर पर अपनी भूमिका को और भी मज़बूत कर सकता है।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-7| July-2026

संदर्भ:

1. Appadorai, A. The Domestic Roots of India's Foreign Policy. Oxford University Press Revised Edition, 1981, pp. 45–67.
2. Dixit, J. N. India's Foreign Policy and Its Neighbours. Gyan Publishing House, First Edition, 2001, pp. 112–135.
3. Pant, Harsh V. Indian Foreign Policy: An Overview. Manchester University Press, First Edition, 2016, pp. 88–110.
4. Cohen, Stephen P. India: Emerging Power. Brookings Institution Press, Second Edition, 2002, pp. 173–201.
5. Tellis, Ashley J. India's Emerging Nuclear Posture. RAND Corporation, First Edition, 2001, pp. 210–248.
6. Chellaney, Brahma. Asian Juggernaut. HarperCollins India, First Edition, 2010, pp. 152–176.
7. Malone, David M. Does the Elephant Dance? Contemporary Indian Foreign Policy. Oxford University Press, First Edition, 2011, pp. 201–235.
8. Bajpai, Kanti P., and Harsh V. Pant. India's National Security: A Reader. Oxford University Press, First Edition, 2013, pp. 95–124.
9. Ganguly, Sumit. Conflict Unending: India–Pakistan Tensions since 1947. Columbia University Press, Second Edition, 2019, pp. 186–214.
10. Rajagopalan, Rajesh. India's Strategic Choices. Routledge India, First Edition, 2014, pp. 131–160.